P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* (Part-1) April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

पंचवर्षीय योजनाओं का महिला सशक्तिकरण में योगदानः एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण

रीतेश यादव
शोधार्थी,
इतिहास विभाग,
आगरा कॉलेज,
आगरा, भारत

सुगम आनंद
आचार्य,
इतिहास विभाग,
डॉ0 भीमराव आंबेडकर
विश्वविद्यालय, आगरा, भारत

सारांश

सशक्तिकरण एवं भौतिक एवं मानसिक अवस्था है जो विशेषकर आंतरिक कुशलताओं और शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों पर आधारित होती है। इसके लिए आवश्यक है कि समाज में न्याय, कानून एवं सुरक्षात्मक प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु जागरूकता हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् एवं भारत विभाजन के दौरान भारत में सामाजिक उथल–पुथल मच गई जिसमें आजादी की खुशी एवं विभाजित भारत के लोगों का शोषण (विशेषकर महिलाओं का) विचारणीय विषय बना। स्वतंत्र भारत में भारत सरकार ने 1951 से पांच वर्षीय योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य किया। इन योजनाओं में भारत सरकार ने महिलाओं के हितों पर भी विशेष ध्यान दिया जिससे कि महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) से लेकर बारहवीं पंच वर्षीय योजना (2012–2017) के बीच महिलाओं को केन्द्र बिन्दु मानकर उनके उत्थान के लिए सरकारें प्रयासरत् रही और कई स्तरों पर इसमें सफलता भी प्राप्त की। निःसन्देह वर्तमान में महिला सशक्तिकरण का जो रूप हमें देखने को मिलता है उसमें कहीं न कहीं भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का भी योगदान है। जिन महिलाओं ने योजनाओं का लाभ उठा लिया वह खुद को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम हो पायी।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण, पंचवर्षीय योजना, स्वतंत्र भारत, विभाजित भारत।

प्रस्तावना

15 अगस्त 1947 को देश ने स्वतंत्रता का सूर्य देखा जो बटवारे के खून से लहूलुहान था। भारत का विभाजन माउंटबैटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वतन्त्र एवं स्वायत्त देश बना दिये जाऐंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी।[1] इसी के साथ 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ की संस्थापना की गई। इससे मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया। विभाजन के बाद महीनों तक दोनों देशों के बीच विशाल जन स्थानान्तरण हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिन्दुओं और सिखों को बलात् बेघर कर दिया गया। लेकिन गाँधी जी के द्वारा कांग्रेस पर दवाब डाला गया और सुनिश्चित किया कि मुसलमान अगर चाहे तो भारत में रह सकते हैं। सीमा रेखा तय होने के पश्चात् करोड़ों लोगों ने हिंसा के डर से सीमा पार करके बहुमत संप्रदाय के देश में शरण ली।

भारत विभाजन से हुई जन, धन की हानि से करोड़ो लोग प्रभावित हुए परंतु जो सर्वाधिक प्रभावित एवं शोषित हुईं वह थी महिलाऐं, क्योंकि महिलाएं अपने परिवार के साथ सड़क पर आ चुकी थीं और उनके साथ, अत्याधिक शारीरिक एवं मानसिक शोषण का व्यवहार किया गया।

आवश्यक था कि विभाजन के घावों पर मरहम लगाया जाये। महिलाओं की सुरक्षा और उन्नति के अवसर मिलें। स्वतंत्रता पश्चात् महिलाओं को विकास के साथ जोड़ने के लिए एवं उनमें जागरूकता लाने के लिए भारत सरकार ने भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान रखे। महिलाओं की उन्नति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक स्वतंत्रता, कानून के संबंध में जागरूकता एवं योजनाऐं बनाई गई ताकि देश के विकास में महिलाऐं पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर अपना योगदान दे सके। यह आसान नहीं था। बहुत सारे

सामाजिक–आर्थिक बंधन थे जिनसे महिलाओं को निकलना था। अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को स्वीकृति प्राप्त नहीं थी।

1947 के बाद, भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं व केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम चलाए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई।[2] प्रधानमंत्री इनके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेहरू ने 8 दिसम्बर 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को पेश किया था। उन्होंने उस समय सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य 2.1 फीसदी निर्धारित किया था। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 कार्यकाल तक तेरहवीं पंचवर्षीय योजना निर्धारित की गई हैं। इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार ने देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पथ को सुनिश्चित करने का भरपूर प्रयास किया। देश के विकास मार्ग को महिलाओं के विकास मार्ग से जोड़ते हुए गया। महिलाओं के हितों पर भी विशेष ध्यान दिया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई थी। महिला कल्याण के मुद्दे इसमें सम्मिलित किए गए थे। इस पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई ताकि इससे महिलाओं के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाया जा सके।[3] प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि स्वतंत्र भारत के बाद भारतीय विकास के शुभारंभ में इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) के अंतर्गत महिला मण्डलों को प्रोत्साहित किया गया ताकि महिलाऐं जमीनी स्तर पर कार्य शुरू कर सकें जिससे कल्याणकारी लक्ष्य प्राप्त हो सकें एवं रोजगार के अवसरों को खोला जा सके।[4] इसी योजना के अंतर्गत 1957 में एक प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रतिभाशाली युवा विद्यार्थियों के परमाणु शक्ति में काम करने के लिए शुरू की गई जिसका लाभ छात्राओं ने भी भरपूर उठाया। तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–1966) में महिला शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया गया एवं उनके स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया गया।[5] इस योजना के बाद 1967–1969 तक कोई नई योजना लागू नहीं की गई। इस समयांतराल को अनवरत योजना कहा गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969 से 1974) के तहत समानता एवं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया जिससे महिलाओं का जीवन स्तर बेहतर हो सके।[6] इस योजना का लक्ष्य वृद्धि 5.6 प्रतिशत और वास्तविक वृद्धि 3.3 प्रतिशत रही।[7]

पंचम पंचवर्षीय योजना (1974–79) के तहत 'कल्याण' शब्द के स्थान पर 'विकास' शब्द को रखा गया। इस दृष्टि से सामाजिक कल्याण का दायरा काफी बढ़ा।[8] इसकी नींव रोजगार, गरीबी उन्मूलन एवं न्याय पर रखी गई थी। इसका लक्ष्य वृद्धि 4.4 प्रतिशत और वास्तविक विकास 4.8 प्रतिशत रहा। यह योजना लक्ष्य प्राप्ति की दृष्टि से सफल रही।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980–1985) के तहत महिला कल्याण विकास को प्राथमिकता दी गई। समुचित महिला विकास हेतु एक पृथक सेक्टर का प्रस्ताव रखा गया।[9]

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–1990) के तहत भी महिला विकास की ओर ध्यान दिया गया और कहा गया कि महिला विकास उसी तरह चलता रहेगा। 'महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक स्थिति में इस प्रकार बदलाव लाया जाए जिससे वे राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सकें।'[10] योजना में 3.9 करोड़ लोगों को रोजगार की श्रम शक्ति में वृद्धि प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद थी। इसकी लक्ष्य वृद्धि 5 प्रतिशत और वास्तविक वृद्धि 6.010 प्रतिशत रही थी।[11]

1989–90 भारत में आर्थिक अस्थिरता की अवधि थी, इसलिए कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गयी। 1990 से 1992 के बीच वहाँ केवल वार्षिक योजनाऐं थी। 1991 में भारत विदेशी मुद्रा भण्डार के संकट की लपेट में था।

आठवीं योजना (1992–97) के काल में भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरूआत थी। उद्योगों का आधुनिकीकरण आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख आकर्षण था। इस योजना के तहत, भारतीय अर्थव्यवस्था एक खुली अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हुई। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल थे– गरीबी में कमी, रोजगार सृजन को नियंत्रित करना, संस्थागत निर्माण, गैर सरकारी संगठन और विकेन्द्रीकरण और लोगों की भागीदारी को मजबूत बनाना।[12] इस पंचवर्षीय योजना के चलते 1993 से 1994 में महिलाओं की भागीदारी स्वरोजगारी में 56.7 प्रतिशत, नियमित रोजगारी में 6.3 एवं अनियमित रोजगारी में 30.1 प्रतिशत रही।[13]

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के माध्यम से तेजी से औद्योगीकरण, मानव विकास, पूर्ण पैमाने पर रोजगार, गरीबी में कमी और घरेलू संसाधनों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया। इस पंचवर्षीय योजना का लाभ सरकार के साथ–साथ जन साधारण लोगों को भी हुआ। इसकी वृद्धि दर 5.35 प्रतिशत थी।[14] इसमें महिलाओं ने भी रोजगार की दृष्टि से वह सारे लाभ उठाए जो पुरूषों ने उठाये। महिलाएं भी रोजगार में अपनी हिस्सेदारी दिखाते हुए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई। 1999 से 2000 के बीच स्वरोजगारी में महिलाओं की भागदारी– 55.6 प्रतिशत, नियमित रोजगारी में महिलाओं की भागीदारी 7.3 प्रतिशत एवं अनियमितत रोजगारी में महिलाओं की भागीदारी 37.1 प्रतिशत रही।[15]

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना एवं गरीबी अनुपात को 15 प्रतिशत कम करना था। इस योजना ने 8.0 प्रतिशत विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा लेकिन वास्तव में 7.2 ही वृद्धि दर हासिल की जा सकी।[16]

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2004–2005 में यदि ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के रोजगार पर प्रकाश डाला जाए तो 2004–05 में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति स्वरोजगारी में 68.7 प्रतिशत, नियमित रोजगारी में 3.7 प्रतिशत, अनियमित रोजगारी 32.6 प्रतिशत थी। इसी

के साथ–साथ शहरी महिलाओं में रोजगारी 47.7 प्रतिशत, नियमित रोजगारी, 35.6 प्रतिशत एवं अनियमित रोजगारी 16.7 प्रतिशत रही।[17]

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रजनन दर को घटाकर 2.1 के स्तर पर लाना, लिंगानुपात को बढ़ाकर 2011–12 तक 935 व 2016–17 तक 950 करना, मातृ मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 करना,[18] जैसे लक्ष्य रखे गये।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 के दौरान वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। इसी के चलते ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर की रफ्तार को 9 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया।[19] इस योजना में महिलाओं के आर्थिक विकास को भी ध्यान में रखा गया। महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया एवं कई प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम चलाये गये।[20]

निष्कर्ष

आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। उपर्युक्त पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से स्पष्ट होता है कि भारत सरकार महिलाओं के समग्र विकास के लिए हर तरह के प्रयास काफी लम्बे समय से करती आ रही है ओर यही कारण है कि आज समाज में महिलाओं की भूमिका में कई तरह के बदलाव दिखाई देने लगे हैं। आज महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता यह दर्शाती है कि महिलाऐं हर क्षेत्र में आगे हैं। परन्तु यह आत्मनिर्भरता सिर्फ शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में देखने को मिलती हैं। ग्रामीण स्तर पर एवं जमीनी स्तर की महिलाओं में यह प्रभाव देखने को नहीं मिलता। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से महिला हितों का ध्यान तो रखा गया, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराए गए, शिक्षा के क्षेत्र में उन पर ध्यान दिया गया, जिससे महिलाएं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ीं। इससे महिलाएं आई0टी0 सेक्टर, बैकिंग, मल्टीमीडिया, पत्रकारिता, डिस्ट्रीब्यूशन, दूरसंचार, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आदि स्थानों पर कार्यरत हैं। महिला उत्थान के लिए जागरूकता फैली परंतु इस जागरूकता का सभी महिलाओं पर प्रभाव देखने को नहीं मिला। शहरी महिलाओं पर ही इसका प्रभाव देखने को मिला। कुछ जागरूक एवं शहरी महिलाएं ही सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का फायदा उठा पाई। आज महिलाओं के हित के लिए योजनाओं की कमी नहीं है बल्कि इन योजनाओं को पूरी तरह क्रियान्वित करने व लाभ उठाने के लिए जागरूकता की कमी है।

केन्द्रीय बजट 2016–17 में महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं पर खर्च के लिए 90,624.76 करोड़ रूपये दिया गया यानि सरकारी खर्च का 4.5 प्रतिशत महिलाओं पर खर्च के लिए आवंटित किया गया है।[21] पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से महिला हितों पर योजनाऐं बनाई तो जा रही हैं परन्तु सभी महिलाओं तक बनाई गई इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। समाज के सतत विकास के लिए जरूरी है कि महिलाओं को जागरूक कर सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। उनकी भागीदारी के स्तर में वृद्धि होने पर ही उनके सशक्तिकरण की भूमिका तय होगी, तभी समाज मजबूत होगा एवं सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा।

पाद टिप्पणी

1. *सुभाष कश्यप (2000) ''भारत का संविधान'' नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, पृ0 22*
2. *स्थिरता के विश्वकोश में सोनी पेलिसरी और सैम गोप।*
3. *गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया 1951, प्लानिंग कमीशन, पहली पंचवर्षीय योजना नई दिल्ली।*
4. *गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया 1956, प्लानिंग कमीशन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना नई दिल्ली।*
5. *गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया 1961, प्लानिंग कमीशन, तृतीय पंचवर्षीय योजना नई दिल्ली।*
6. *गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया 1969, प्लानिंग कमीशन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना नई दिल्ली।*
7. *http://hi.m.wikipedia.org*
8. *गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया 1974, प्लानिंग कमीशन, पंचम पंचवर्षीय योजना नई दिल्ली।*
9. *गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया 1980, प्लानिंग कमीशन, छठी पंचवर्षीय योजना नई दिल्ली।*
10. *गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया 1985, प्लानिंग कमीशन, सातवीं पंचवर्षीय योजना नई दिल्ली।*
11. *http://hi.m.wikipedia.org.*
12. *गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया 1992, प्लानिंग कमीशन, आठवीं पंचवर्षीय योजना नई दिल्ली।*
13. *EPW Research Foundation in India : A Pocket Book of Data Series 2012 (Delhi 2012) Table 16.9. P 175 and NSSO 68th Round Employment – And unemployment in India 2011-12 June 2013, Table No. P-18*
14. *गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया 1997, प्लानिंग कमीशन, नवीं पंचवर्षीय योजना नई दिल्ली।*
15. *EPW Research Foundation in India : A Pocket Book of Data Series 2012 (Delhi 2012) Table 16.9. P 175 and NSSO 68th Round Employment – And unemployment in India 2011-12 June 2013, Table No. P-18*
16. *https://m.jagranjosh.com*
17. *EPW Research Foundation in India : A Pocket Book of Data Series 2012 (Delhi 2012) Table 16.9. P 175 and NSSO 68th Round Employment – And unemployment in India 2011-12 June 2013, Table No. P-18*
18. *गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया 2007, प्लानिंग कमीशन, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना नई दिल्ली।*
19. *https://www.hindyojna.in*
20. *गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया 2012, प्लानिंग कमीशन, बारहवीं पंचवर्षीय योजना नई दिल्ली।*
21. *www.indiagov.in*